

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2025—वैशाख 26, शक 1947

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2025

क्र. एफ 1-41-2018-ब-2-दो—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री रजत सकलेचा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला को दिनांक 19 मई से 6 जून 2025 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 23 मई से 2 जून 2025 तक की अवधि में पत्नी श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे के साथ फ्रांस (यूरोप) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

- विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) श्री रजत सकलेचा, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला का कार्य प्रभार श्री अमित वर्मा, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रजत सकलेचा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री रजत सकलेचा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री रजत सकलेचा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत सकलेचा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2025

क्र. 1-1-1-0106-2025-ब-2-दो.—श्रीमती श्रद्धा तिवारी, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2024 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश का लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अन्तर्गत परिवार सहित मथुरा, वृन्दावन उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जाने एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) अतः, अवकाश यात्रा रियायत नियम 1975 के नियम 12 के अंतर्गत पत्नी के साथ यात्रा करने पर श्री संजय तिवारी, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, (योजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को सम्मिलित करते हुए इन्हें भी दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2025

क्र. एफ 1-1-1-0167-2025-ब-2-दो—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मनीष भारद्वाज, परिवीक्षाधीन, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सतना को प्रशिक्षण उपरांत प्राप्त होने वाले ज्वाइनिंग टाईम / अवकाश अवधि दिनांक 17 से 24 मई 2025 तक उक्त अवधि में Switzerland Europe की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: —

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष भारद्वाज, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष भारद्वाज, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष भारद्वाज, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2025

फा. क्र. 1886-2025-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री निलेश यादव, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग का उच्च न्यायिक सेवा के पद से दिया गया त्याग-पत्र दिनांक 1 मई 2025 से स्वीकार करता है.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2025

फा. क्र. 1693-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में श्री निलेश यादव, अधिवक्ता (MP/1950/2002) को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2025

फा. क्र. 1951-2025-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन पाराशर, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के दिल्ली स्थित कार्यालय में रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 863-Confdl-2025-II-2-41-95 दिनांक 28 अप्रैल 2025 में वर्णित अनुदेशों के अध्याधीन सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2025

क्र. 4668-1531-इक्कीस-अ(स्था.).—कार्यालय, उप-नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, मध्यप्रदेश से वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) (600 प्रतियां) की छपाई कार्य, जिसका देयक क्र. 18978, दिनांक 8-4-2025 (सी. जी. एस. टी. एवं एस. जी. एस. टी. राशि रुपये 19,378+3,488=22,866) सहित कुल राशि रुपये 22,866/- (रुपये बाईस हजार आठ सौ छियांसठ केवल) की भुगतान स्वीकृति प्रदान की जाती है.

उक्त व्यय मांग संख्या-29-2052-00-090-9999-9057-v-22-कार्यालय व्यय की उपमद-012-मुद्रण एवं प्रकाशन में से वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव.

**वन विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 मई 2025

क्रमांक/PCCF/7/0181/2025-FLR-PCCF :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

**अनुसूची**

**जिला-बालाघाट**

**तहसील - कटंगी**

**वनमंडल-दक्षिण बालाघाट (सा.)**

**वन परिक्षेत्र- वारासिवनी (सा.)**

अ.क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	टेकाडी (द)	टेकाडी	शासकीय भूमि, घास चराई	356/2	8.000	उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 3 और मुनारा क्र. 3 से आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष क्र. 481 के मुनारा क्र. 12/1 तक कृत्रिम वनसीमा। पूर्व- आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष क्र. 481 के मुनारा क्र. 12/1 से मुनारा क्र. 14/1 तक की वनसीमा।
				योग-	8.000	दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड सोनेवानी के कक्ष क्र. 481 के मुनारा क्र. 14/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 एवं मुनारा क्र. 4 से मुनारा क्र. 6 तक की कृत्रिम वनसीमा।

						पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से मुनारा क्र. 9 और मुनारा क्र. 9 से मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
--	--	--	--	--	--	--

**(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 019/2023-बीएचओ दिनांक 05.11.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग/संस्थान- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1, 2 बालाघाट, जिला बालाघाट अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना कांद्रीकला से कट्टीपार तक सड़क निर्माण कार्य प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/155493/2022 में प्रभावित वनभूमि रकबा 7.470 हे० के एवज में उपरोक्त अनुसूची अनुसार प्राप्त कुल 8.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0032/अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

**2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक**

**(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार कटंगी, जिला-बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-**

1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मई 2025

क्र. PCCF-7-0181-2025-FLR-PCCF.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF-7-0181-2025-FLR-PCCF, दिनांक 13 मई 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 13<sup>th</sup> May 2025

No./PCCF/7/0181/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below. subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

## SCHEDULE

District:- Balaghat

Tahsil :- Katangi

Forest Division :- South Balaghat

Forest Range :- Waraseoni

S.No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area ( Hectare)	
1	Tekadi (D)	Tekadi	Government Land, Ghas Charai	356/2 Total	8.000 8.000	North- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 3 of the proposed protected forest block and from Pillar No. 3 to 12/1 of Compartment No. 481 of reserved forest block Sonewani. East- Forest boundary from Pillar No. 12/1 to Pillar No. 14/1 of Compartment No. 481 of reserved forest block Sonewani. South- Artificial forest boundary from Pillar No.14/1 of Compartment No. 481 of reserved forest block Sonewani to Pillar No. 4 of proposed protected forest block and from Pillar No. 4 to 6. West- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to Pillar No. 9 and Pillar No. 9 to Pillar No. 1 of the proposed protected forest block.

## (A) Reason for Publication of Notification :-

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 6-MPR 019/2023-BHO dated 05-11-2024 and in lieu of 7.470 hectare of forest land affected in construction of road from Kandrikala to Kattipar, proposal No. FP/MP/Road/155493/2022 of user agency- General Manager, M.P.R.R.D.A., PIU-1, 2 Balaghat, Distt. Balaghat, the Non Forest Land of 8.000 hectare as mentioned in the schedule above, transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. /R.P.K./0032/A-59 year 22-23 dated 05.12.2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation is to be

declared as protected forest.

1. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Competent Revenue officer report (Certificated) of Tahsildar- Katangi, District- Balaghat are as under.

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy. Secy.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन भोपाल, दिनांक 6 मई 2025

क्र. एफ-1-1-25-रा. स.-यू. ए. 1-475.—अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 29 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु कम-से-कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :—

1.	प्रो. अर्पण भारद्वाज, कुलगुरु, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म. प्र.).	समिति के अध्यक्ष	कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट
2.	प्रो. मजहर आसिफ, कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025.	समिति के सदस्य	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, द्वारा नामनिर्दिष्ट.
3.	प्रो. (डॉ.) आशुतोष कुमार सिंह, निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (म. प्र.).	समिति के सदस्य	कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट.
4.	डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया, (पूर्व कुलाधिपति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वि. वि., लखनऊ) भोपाल (म. प्र.).	समिति के सदस्य	राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट.

(2) कुलाधिपति के द्वारा प्रो. अर्पण भारद्वाज, कुलगुरु को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

(4) समिति पैनल तैयार करने में कुलगुरु की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022-रास-यू. ए. 1, दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार,  
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, मध्यप्रदेश, राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

बी 'विंग' भूतल, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 2025

ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत

क्र. सह. अधि.-स्था.-2025-609.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 21 मई 2025 से 13 जून 2025 तक, में से 15 दिनों का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 26 से 30 मई 2025 तक (पांच दिन) एवं दिनांक 4 से 13 जून 2025 तक (दस दिन) तक इस प्रकार कुल पन्द्रह दिनों तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

वैशाली जैन, रजिस्ट्रार.

## राज्य शासन के आदेश

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-15-1-2021-सात-शा. 7

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित पूर्व वन ग्राम के अनुसूची कालम नंबर (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निर्वनीकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की गई है अतः राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) खण्ड (ब-5) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कालम क्रमांक (2) में वर्णित हस्तान्तरित वन ग्राम को कालम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करती है :-

अनुसूची  
जिला- नर्मदापुरम

क्र. मां. क्र.	पूर्व वनग्राम का नाम / वन परिक्षेत्र	तहसील का नाम	नवीन राजस्व ग्राम का नाम	वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तान्तरित क्षेत्रफल (हे०) में	वनग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए चतुर्सीमाएं				वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म०प्र० शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)
1	काजरी	सोहागपुर	नया काजरी	170.000	शासकीय ख.न. 297	जंगल सरकार	परसवाडा	शासकीय ख.न. 297	क्रमांक 800667 / 2022 / 10-3 दिनांक 30. 12.2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 23 अप्रैल 2025

क्र. 46-भू-अर्जन-2025.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस हेतु अनुसूची के कालम क्रमांक (4) में वर्णित भूमि का आपसी सहमति से क्रय नीति के तहत धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जित रकबा क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बालाघाट	बैहर	अलना	0.905	पारधी मोहल्ला सड़क निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मैहर, दिनांक 11 सितम्बर 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र. 11-भू-अर्जन-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
मैहर	रामनगर	बेलहाई	1.2	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि., संभाग रीवा (म. प्र.).	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लि., संभाग रीवा, रामनगर भरतपुर (भैसरहा) से गोविन्दगढ़ वाया जिगना टू लेन विथ पेव्ड शोल्डर डामरीकृत निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 मई 2025

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2025-2026.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी भूमि रकबा 1.2972 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.1704 हे. कुल रकबा 1.4676	उप मुख्य अभियंता/नि. -द्वितीय पश्चिम मध्य रेलवे, सतना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु (पूरक / छूटे हुए रकबों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण-द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे, सतना, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.







क्र. 4013-भू-अर्जन-2025-प्र. क्र. 12-अ-82-अविअ-2023-24.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरस बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम नयाखेडा, तहसील देवरी के कृषकों को निजी भूमियों का भू-अर्जन हेतु “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है। अर्जित भूमियों के संबंध में भू-स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है।

अतः चिंकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरस बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम नयाखेडा, तहसील देवरी जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय (अवार्ड) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास (6 माह) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है।

क्र. 4012-भू-अर्जन-2025-प्र. क्र. 10-अ-82-अविअ-2023-24.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रायसेन जिले के अन्तर्गत चिंकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरस बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम टिमरावन, तहसील देवरी के कृषकों को निजी भूमियों का भू-अर्जन हेतु “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के तहत अर्जित की जाने वाली भूमियों का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024 में प्रकाशन किया गया है। अर्जित भूमियों के संबंध में भू-स्वामियों द्वारा दावे / आपत्ति प्रस्तुत करने से उनके निराकरण एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनिर्णय पारित किये जाने में समय लगने की संभावना है।

अतः चिंकी बोरस बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना अन्तर्गत बोरस बराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम टिमरावन, तहसील देवरी जिला रायसेन के कृषकों की निजी भूमियों का अर्जन के लिये प्रकरण में अधिनिर्णय (अवार्ड) पारित किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने में समय लगने के कारण “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 25 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचना जारी दिनांक से निरन्तर छः मास (6 माह) के लिये समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 1 अप्रैल/मई 2025

मौजा मण्डी बामौरा, पट. ह. नं. 65, तहसील बीना

(धारा 6 देखिए)

क्र. 0004-अ-82-24-25-भू-अर्जन-25-3985.—कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, सागर संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार भोपाल, बीना-रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 957/16-18 में समपार क्रमांक 300 (मण्डी बामोरा) पर कुरवाई-गुदावल मार्ग के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य हेतु समुचित सरकार प्रभावित ग्राम मण्डी बामौरा पट. हल्का नंबर 65 तहसील बीना, जिला सागर की भूमि कुल रकबा 1.150 हे. का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरान्त मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:— प्ररूप ख एवं ग

संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**प्रारूप-ख**  
**(नियम 5 देखिए)**

**सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट**

1. परियोजना का नाम : सागर जिले के भोपाल-बीना रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 957/16-18 में समपार क्रमांक-300 (मण्डीबामोरा में) पर एवं कुरवाई-गुदावल मार्ग के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य.
2. लोक प्रयोजन : आम जन के सुगम आवागमन हेतु मण्डीबामोरा में भोपाल-बीना रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 957/16-18 में समपार क्रमांक-300 (मण्डीबामोरा में) पर एवं कुरवाई-गुदावल मार्ग के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य.
3. स्थल : मौजा मण्डीबामोरा में खसरा नं. 190/1, 190/2, 190/3, 109/4, 190/5, 190/6, 193, 58/2/1/2, 58/2/1/2, 58/2/1/2, 58/2/1/2, 58/2/2, 194/1/1, 194/1/1, 194/1/2, 194/2/1, 194/2/2, 194/3/1, 35, 28 भूमि है.
4. परियोजना का क्षेत्र : तहसील बीना के मौजा मण्डीबामोरा में खसरा नं. 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 193, 58/2/1/2, 58/2/1/2, 58/2/1/2, 58/2/1/2, 58/2/2, 194/1/1, 194/1/1, 194/1/2, 194/2/1, 194/2/2, 194/3/1, 35, 28 में रकबा क्रमशः 0.22 हे., 0.09 हे., 0.07 हे., 0.08 हे., 0.11 हे., 0.015 हे., 0.06 हे., 120 वर्गफुट (11.148 मी.), 120 वर्गफुट (11.148 मी.), 90 वर्गफुट (8.36 मी.), 120 वर्गफुट (11.148 मी.), 180 वर्गफुट (16.723 मी.), 0.11 हे., 492.5 वर्गफुट (45.75 मी.), 492.5 वर्गफुट (45.75 मी.), 0.03 हे. 0.03 हे., 0.015 हे., कुल प्रभावित 0.05 हे. में से 3.601 वर्गमीटर में मंदिर की पक्की दीवार 49.60 वर्गमीटर में पक्की दुकान एवं 17 वर्गमीटर में रास्ता, भूमि प्रभावित है.
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया : प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त आर. ओ. बी. निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.
6. विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित : कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर
7. परियोजना निर्माण के चरण : निर्माण कार्य प्रथम चरण में हैं जिसमें रेल्वे क्षेत्र में रेल्वे का कार्य प्रगति पर है. भू-अर्जन उपरांत आर. ओ. बी. का निर्माण कार्य दुरुस्त गति से पूर्ण कर लिया जावेगा.
8. परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे : संलग्न है
9. परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि : 0.98 हे. एवं 216.627 वर्गमीटर
10. भूमि का मूल्य : वर्ष 2024-25 की गाईड लाइन के आधार पर
11. प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या : 20

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 12. | परिसम्पत्तियों :                                 | मकान, दुकान, बाउण्ड्रीवॉल, समाधि.   |
| 13. | विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या : | निरंक   |
| 14. | सामाजिक समाघात :                                 | निरंक   |
| 15. | विकल्प जिन पर विचार किया गया                     | प्रभावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है  |
| 16. | निष्कर्ष :                                       | प्रस्तावित भूमि पर आर. ओ. बी. निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा. तथा आमजन को आवागमन की सुविधा होगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा. अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है. |

#### प्रारूप-ग

(नियम 5 देखिए)

#### सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | प्रभावित परिवारों की जीविका :   | अप्रभावित  |
| 2.  | लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों :   | अप्रभावित  |
| 3.  | आस्तियों और अधोसंरचना विशेषकर सड़क, लोक परिवहन.   | : अप्रभावित  |
| 4.  | जल-मल निकासी एवं स्वच्छता :   | अप्रभावित  |
| 5.  | पेयजल के स्रोत :  | अप्रभावित  |
| 6.  | पशुओं के लिए जलस्रोत :  | अप्रभावित  |
| 7.  | सामुदायिक तालाब :   | अप्रभावित  |
| 8.  | जन सुविधाएं :   | 1. खसरा नं. 35 में मंदिर की बाउण्ड्री वॉल प्रभावित है.<br>2. खसरा नं. 190/1 में प्रभावित भूधारकों के पूर्वजों की समाधि स्थल प्रभावित है. |
| 9.  | वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा. | : आर. ओ. बी. में डक्ट, आर. ई. वॉल एवं नाली निर्माण का प्रावधान किया गया है. जिससे जनता को आवागमन में सुविधा रहेगी.                       |
| 10. | अतिरिक्त उपाय :   | अपेक्षक निकाय सहमत है.   |

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-3915-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0083-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 8 मई 2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है।

### --अनुसूची(1)--

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य	0.223

### --अनुसूची(2)--

#### (1) भूमि का विवरण

(क) जिला	:- उज्जैन
(ख) तहसील	:- कोठीमहल
(ग) ग्राम	:- नानाखेड़ा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल	:- 0.223

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा(हेक्टेयर में)	धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	81/2/6	0.003	संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र.)	उज्जैन सिंहस्थ बायपास 4-लेन मय मार्ग पेव्ड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य
2	81/2/5/1	0.062		
3	81/2/1/4	0.032		
4	80/5/1/1/1	0.063		
5	80/5/1/3	0.063		
कुल रकबा		0.223		

अधिनियम की धारा-15(1) अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग कोठीमहल के समक्ष आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग कोठीमहल कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-3918-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.0083-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में इंगोरिया-उन्हेल मार्ग के मध्य 2-लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य इंगोरिया-उन्हेल मार्ग के मध्य 2-लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है। साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-:अनुसूची (1) :-

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
इंगोरिया-उन्हेल मार्ग के मध्य 2-लेन पेव्ड शोल्डर निर्माण हेतु	1.5394 हेक्टर

-:अनुसूची (2) :-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- बड़नगर

(ग) ग्राम

:- पलसोड़ा

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

:- हेक्ट. अनुसूची (1) अनुसार

क्र० सं०	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)	धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी-	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05
1	21/1/1	0.1200	संभागीप्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र.)	इंगोरिया-उन्हेल मार्ग के मध्य 2-लेन पेहड शोल्डर निर्माण हेतु
2	21/1/2	0.1600		
3	21/2	0.1600		
4	21/3	0.1420		
5	21/4	0.0700		
6	21/5	0.2200		
7	21/6	0.2000		
8	124/629/1	0.0040		
9	124/629/2	0.0060		
10	125	0.0100		
11	126	0.1220		
12	127/1	0.1230		
13	127/2	0.2000		
14	124/1	0.0024		
कुल रकबा		1.5394		

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील बडनगर जिला उज्जैन के समक्ष में आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तहसील बडनगर जिला उज्जैन कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प.क्र.-16-भू-अर्जन-2025

मऊगंज, दिनांक 24 अप्रैल 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम-भलुहा, राजस्व निरीक्षक मण्डल-नईगढ़ी, पटवारी हल्का-भलुहा-30, तहसील-नईगढ़ी, जिला-मऊगंज, मऊगंज जिले के ग्राम भलुहा से ग्राम हर्दी तिवरियान मार्ग में कटरिया नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

### अनुसूची

#### भूमि का वर्णन

(क) जिला — मऊगंज (म.प्र.) (ख) तहसील — नईगढ़ी  
(ग) नगर/ग्राम — भलुहा (घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.519 हेक्टेयर

खसरा एवं रकबा का विवरण				खसरा एवं रकबा का विवरण			
क्र.	खसरा नं.	भूमि स्वामियों का नाम	अर्जित रकबा (हे. मे)	क्र.	खसरा नं.	भूमि स्वामियों का नाम	अर्जित रकबा (हे. मे)
1	1575	कौशल प्रसाद, रामलखन, रामसखा पिता लक्ष्मण प्रसाद, पटेल	0.053	13	1587	पीताम्बर, नन्दलाल पिता वैजनाथ पटेल	0.023
2	1588/1		0.017	14	1576/2		0.018
3	1582		0.050	15	1577/1	इन्द्रलाल पिता राजदेव पटेल	0.016
4	1581/2		0.016	16	1652	रामसिया, भैयालाल पिता सरजो	0.025
5	1549		0.063	17	1587/2	हर प्रसाद पिता जानकी पटेल	0.013
6	1651		0.014	18	1650/1	हर्षलाल, अर्जन पिता अनन्दे, रामलाल पिता रामधनी जायसवाल	0.023
7	1607		0.015	19	1605	रामलाल पिता रामधनी	0.023
8	1971		0.013	20	1606/1	रामगोपाल, रामलाल पि0 रामधनी जैस0	0.021
9	1608/2		0.033	21	1578	वंशराखन त्रिवेणी पिता शुदर्शन पटेल	0.025
10	1586	अशोक कुमार	0.019				
11	1583	पिता अग्रसेन	0.022				
12	1588/2	पटेल	0.017			कुल योग 21 किता	0.519 हे.

- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- मऊगंज जिले के ग्राम भलुहा से ग्राम हर्दी तिवरियान मार्ग में कटरिया नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला मऊगंज एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## न्यायालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली, जिला देवास, मध्यप्रदेश

बागली (देवास), दिनांक 22 अप्रैल 2025

प्ररूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालनयंत्री जल संसाधन विभाग देवास के पत्र क्रमांक - 695 दिनांक 21/02/2025 के अनुसार राज्य सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले में ग्राम गोला तहसील हाटपिपल्या में " मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम गोला में भूमिगत पाइपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा :-

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	8	9
1	मोहनसिंह पुत्र खुशलसिंह उर्फ खुशीलाल जाति सेंधव, नरेंद्रसिंह पुत्र खुशलसिंह उर्फ खुशीलाल जाति सेंधव, कविताबाई पुत्री खुशलसिंह उर्फ खुशीलाल जाति सेंधव,	28	2.580	0.1233	-
		28	2.580	0.1233	-

1 जिले का नाम - देवास

2 तहसील- हाटपिपल्या

3 ग्राम- गोला

4 खसरा क्रमांक- 28

5 भूमि का रकबा (हे. में) 2.580 हे. में से (अर्जित रकबा ) - 0.1233 हे.

6 भूमि - सिंचित

7 अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8 किस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है - आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-II लिफ्ट माइक्रो उद्भवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 110000 हे. कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

आनंद मालवीया, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व).

## न्यायालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश

टोंकखुर्द (देवास), दिनांक 6 मई 2025

प्ररूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म.प्र. के पत्र क्रमांक 1089 दिनांक 25/03/2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम रायपुर तहसील टोंकखुर्द में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट(भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम रायपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट(भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल(हे. मे)	भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	भारत सिंह पिता उमराव सिंह	474	0.3000	0.060	
		474	0.3000	0.060	

1- जिले का नाम - देवास

2- तहसील - टोंकखुर्द

3- ग्राम - रायपुर

4- खसरा क्रमांक - 474

5- भूमि का रकबा(हे.मे) 0.3000 हे. मे से(अर्जित रकबा) 0.060 हे.

6- भूमि - सिंचित

7- अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन कर जा रही है - आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

प्ररूप- "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2) के तहत]

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास विभाग संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगौन म.प्र. के पत्र क्रमांक 1076 दिनांक 25/03/2025 के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी जिसके लिए आवश्यक जल परिवहन हेतु देवास जिले के ग्राम चौबाराधीरा तहसील टोंकखुर्द में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट(भूमि की उपयोगिता के अधिकारोका अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत ग्राम चौबाराधीरा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाना है।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट(भूमि की उपयोगिता के अधिकारोका अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित आक्षेप भेज सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र.	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल(हे. मे)	भूमिगत पाईपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के लिए अपेक्षित भूमि (हे. मे)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	समंदरसिंह पिता भेरुसिंह	2055	0.9600	0.080	—
		2055	0.9600	0.080	—

1- जिले का नाम - देवास

2- तहसील - टोंकखुर्द

3- ग्राम - चौबाराधीरा

4- खसरा क्रमांक - 2055

5- भूमि का रकबा(हे.मे) 0.9600 हे. मे से(अर्जित रकबा) 0.080 हे.

6- भूमि - सिंचित

7- अर्जित भूमि में स्थित अन्य संपत्ति - निरंक

8- किस कार्य के लिए भूमि अर्जन कर जा रही है - आई.एस.पी. कालीसिंध चरण-1। लिफ्ट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शाजापुर और राजगढ़ जिले में जल परिवहन के लिए 1,10,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

कन्हैयालाल तिलवारी, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

रा.प.क्र.-13-अ-82-2023-24

दमोह, दिनांक 22 अप्रैल 2025

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रं० 12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर को "दमोह जिले के दमोह-हिन्दोरिया-पटेश मार्ग पर बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1133/8-9 के समपार क्रमांक-65 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित)" हेतु मौजा समन्ना माल पटवारी हत्का नं. 5 तहसील दमयंती नगर (दमोह नगर) के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भू स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम:- दमोह-हिन्दोरिया-पटेश मार्ग पर बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1133/8-9 के समपार क्रमांक-65 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित)"।  
ग्राम का नाम :- समन्नामाल तहसील दमयंतीनगर अर्जित रकबा 0.42 हे.

**आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण**

क्र०	भूस्वामी / पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा	अन्य सम्पत्ति
1.	भुरलीमनोहर, राजकुमार पिता नाथूराम संतोषरानी बेवा नाथूराम सा.देह समन्ना माल तहसील दमोह नगर	529/1/4	0.50 हे.	0.13 हे.	
2.	रामचरण पिता दयाराम अहिश्वार सा.देह समन्ना माल तहसील दमोह नगर जिला-दमोह	529/1/3	0.51 हे.	0.15 हे.	
3.	श्रीमति रईसा बेगम पति नवीबक्श जाति मुसलमान सा. देह समन्ना माल तहसील दमोह नगर जिला-दमोह	528/1	0.80 हे.	0.14 हे.	
		03	1.81 हे.	0.42 हे.	

रा.प.क्र.-14-अ-82-2023-24

दमोह, दिनांक 25 अप्रैल 2025

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रं० 12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर को "दमोह जिले के दमोह-हिन्दोरिया-पटेरा मार्ग पर बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1133/ 8-9 के समपार क्रमांक-65 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित)" हेतु मौजा करैयाहजारी पटवारी हल्का नं. 39 तहसील दमोह के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भू स्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

**सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।**

**योजना का नाम:-** दमोह-हिन्दोरिया-पटेरा मार्ग पर बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1133/8-9 के समपार क्रमांक-65 के ऐवज में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित)।

**ग्राम का नाम :-** करैयाहजारी तहसील दमोह अर्जित रकबा 0.4455 हे.

**आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण**

क्र०	भूस्वामी / पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा	अन्य सम्पत्ति
1.	श्री ऋषि पिता बाबूलाल सा.देह करैया हजारी तहसील दमोह	10/4	0.600 हे.	0.097 हे.	
2.	श्री नारान पिता वैजनाथ अहिरवार सा.देह करैया हजारी तहसील दमोह	11/1/1/2/1	0.030 हे.	0.0125 हे.	
3.	श्री प्रिन्स पिता दीपचंद असाठी सा.देह करैया हजारी तहसील दमोह	11/1/1/2/2	0.200 हे.	0.05 हे.	
4.	श्रीमति सरस्यती पति बाबूलाल अहिरवार सा.देह करैया हजारी तहसील दमोह	17/4/2/2	0.06 हे.	0.036 हे. (पड़ती)	
5.	हरिदास, लखन पिता शंकर सा.देह करैया हजारी तहसील दमोह	208/2	0.03 हे.	0.005 हे. (पड़ती)	
6.	श्री जय कुमार पिता गोकुल जैन सा.देह करैया हजारी तहसील दमोह	216/1	0.76 हे.	0.245 हे. (पड़ती)	

रा.प.क्र.-01-अ-82-2024-25

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रं० 12-2-2014/सात/ए/भोपाल, दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर को "दमोह जिले के दमोह-कटनी मार्ग पर बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1137/1-3 के समपार क्रमांक-67 में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित)" हेतु मौजा भदौली पटवारी हल्का नं. 36 तहसील दमोह के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भू स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र 'ख' में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।

योजना का नाम:- दमोह-कटनी मार्ग पर बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1137/1-3 के समपार क्रमांक-67 में आर.ओ.बी. का निर्माण (पहुंचमार्ग सहित)"

ग्राम का नाम :- भदौली पटवारी हल्का नं. 36 तहसील दमोह अर्जित रकबा 0.656 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क्र०	भूस्वामी / पिता का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जित रकबा	अन्य सम्पत्ति
1.	सीताराम पिता सुंदर जाति यादव सा.देह भदौली तहसील दमोह	702/1	0.19 हे.	0.04 हे.	-
2.	नरेन्द्र कुमार पिता देवीप्रसाद सा.देह भदौली तहसील दमोह	702/2	1.17 हे.	0.355 हे.	-
3.	नरेन्द्र कुमार, विजय, जानकी, शशि पिता देवीप्रसाद सा.देह भदौली तहसील दमोह	703	1.57 हे.	0.015 हे.	-
4.	राजू पिता मिठू, जगदीश पिता नन्नु सा.देह भदौली तहसील दमोह	711/3	0.37 हे.	0.158 हे.	-
5.	बहोरा पिता गोकल जाति काछी सा. देह भदौली तहसील दमोह	715/1	0.15 हे.	0.007 हे.	-
6.	सोनेलाल पिता तुलसीराम जाति काछी सा.देह भदौली तहसील दमोह	716/6	0.08 हे.	0.066 हे.	-
7.	सोनेलाल पिता तुलसीराम जाति काछी सा.देह भदौली तहसील दमोह	716/7	0.04 हे.	0.015 हे.	-

सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 09-अ-82-2024-25

राजगढ़, दिनांक 9 मई 2025

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील-सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-बेराड के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

### -: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : सुठालिया

जिला : राजगढ़

**सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, बेराड**

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मै)
		रकबा
( 1 )	( 2 )	( 3 )
1	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-बेराड की शेष भूमि की आवश्यकता।	0.375
	कुल योग :	0.375

### -: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	रामप्रसाद पिता भंवरलाल जाति काछी पता ग्राम बेराड तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	144/1	0.285	0.285
	योग :-	कुल 1 किता	0.285	0.285
2	कमलसिंह पिता रामप्रसाद जाति काछी पता ग्राम बेराड तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी	143/1/1/1	0.090	0.090
	योग :-	कुल 1 किता	0.090	0.090
	महायोग :-	कुल 02 किता	0.375	0.375

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।



प्र.क्र. 01-अ-82-2024-25

राजगढ़, दिनांक 24 अप्रैल 2025

(अंतर्गत धारा - 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामपुरिया जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ रामपुरिया जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## --: अनुसूची ( 1 ) :-

## रामपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का भू-अर्जन प्रकरण

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		कुल सर्वे नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1	रामपुरिया	9	4.037	0.970
कुलयोग :-		9	4.037	0.970

## --: अनुसूची ( 2 ) :-

## रामपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर में प्रभावित भूमि :- ग्राम रामपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	देवेन्द्र पिता नारायणसिंह नाबा. सरपरस्त माता अनुसुईयाबाई पति नारायणसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	17/13/1	0.119	0.038
	योग	1	0.119	0.038
2	रतन उर्फ रतनसिंह पिता कालूसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	17/21	0.745	0.097
	योग	1	0.745	0.097
3	कालूसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	17/30	0.133	0.012
	योग	1	0.133	0.012
4	बल्लभबाई पति अनारसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	17/39/1	0.511	0.126
	योग	1	0.511	0.126
5	बालूसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	17/40	1.265	0.178
	योग	1	1.265	0.178
6	भेरूसिंह पिता रामलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	17/41/1 17/41/3	0.212 0.420	0.202 0.103
	योग	2	0.632	0.305
7	कमलाबाई पति बीरमसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी	17/41/2 17/41/4	0.212 0.420	0.177 0.037
	योग	2	0.632	0.214
	कुल योग :-	9	4.037	0.970

नोट :- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर,

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं सक्षम प्राधिकारी खण्डवा,  
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश**

प.क्र.-2143-रीडर-1-2025-रा.प्र.क्र.0025-बी-121-2024-25

खण्डवा, दिनांक 14 मई 2025

प्ररूप- "घ"  
{नियम-6 देखिए}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 2570/ री-1/2024, खण्डवा, दिनांक 09.08.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- छैगांव माखन, जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.08.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	छैगांव माखन	ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37,	212	0.026
			213	0.066
			15	0.105
			105/1	0.079
			210/1	0.084

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	छैगांव माखन	ग्राम— बरुड़, प.ह.नं.— 24 / 37,	231	0.029
				0.013
			233	0.015
				0.052
			234	0.016
			235	0.011
			247/1	0.182
			302/1	0.082
			313	0.052
			303	0.046
			259	0.051
			261/1	0.018
			261/2	0.024
			265	0.018
			264	0.024
			268/1	0.070
			268/2	0.048
			269	0.038
			236	0.011
			314	0.031
			349/2	0.062
				0.032
			349/1	0.081
				0.042
			350	0.028
			353/1	0.084
			353/2	0.041
			358	0.079
			1414	0.022
				0.021
			360	0.066
			363	0.036
			1058/1	0.008
				0.032

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	छैगांव माखन	ग्राम— बरुड़, प.ह.नं.— 24 / 37,	364	0.075
			367/2/2	0.127
			339	0.064
			345/2	0.052
			345/3/1	0.064
			346	0.016
			347/2	0.022
			349/3	0.024
			1398/1	0.008
			716	0.035
			718/2	0.006
			718/5	0.026
				0.019
			718/3	0.027
			718/6	0.018
			718/4	0.027
			720	0.034
			721/1	0.048
			729	0.008
			735/2	0.050
			736	0.026
			754/1	0.048
			754/2	0.026
			754/3	0.014
			755	0.066
			758	0.021
			759	0.021
			760	0.021
			763	0.029
			764/1	0.032
			764/2	0.008
			765	0.028
			1312	0.088
			1314	0.030
			1383/2	0.016
			1384/1	0.024
			1411	0.027
			351	0.044

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	छैगांव माखन	ग्राम— बरुड़, प.ह.नं.— 24 / 37,	237/1	0.018
			237/2	0.006
			237/3	0.018
			238	0.018
			987/1	0.030
			633/1/1	0.030
			987/2	0.032
			986	0.008
			991/1	0.006
			993/2	0.048
			993/1	0.003
			995	0.029
			996	0.016
			999/3	0.014
			999/2	0.038
			1002	0.051
			1033	0.019
			1039/2	0.024
			1040	0.017
			1041	0.040
			637/2	0.042
			697	0.042
			1427	0.029
			1442	0.012
			1443	0.022
			1444	0.046
			1447	0.066
			1448/2	0.005
			1457	0.032
			1473	0.016
			1458	0.016
			1459/1	0.016
			1459/2	0.020
			1459/3	0.019
			1460	0.008
			1474	0.042
			591/4	0.019
			630	0.014
			592	0.027

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	छैगांव माखन	ग्राम— बरुड़, प.ह.नं.— 24 / 37,	631	0.018
			887	0.040
			892	0.008
			893	0.026
			896	0.022
			897	0.043
			906	0.109
			907	0.032
			908	0.018
			909	0.027
			1048	0.019
			1049/1	0.027
			1049/2	0.018
			1049/3	0.013
			1055	0.024
			1056/1	0.019
			2364	0.016
			2377	0.056
			2378	0.034
कुल योग			128	4.671

बजरंग बहादुर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).